

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 184
जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

.....

शहरी क्षेत्र में भूजल स्तर

184. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के शहरी क्षेत्रों में जलस्तर की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) शहरी क्षेत्रों में कुओं के जलस्तर में कितने प्रतिशत की कमी आई है;
- (ग) जलस्तर में गिरावट के लिए उत्तरदारी कारकों का ब्यौरा क्या है और इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या शहरी क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण और जल-संतुलन पर भूमि उपयोग की बदलती पद्धति के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई आकलन किया जा रहा है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भविष्य में ऐसा कोई अध्ययन का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा मानीटरिंग कूपों के एक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर कुछ चिन्हित शहरी क्षेत्रों/नगरों सहित पूरे देश में आवधिक रूप से भूजल स्तर की मानीटरिंग की जा रही है।

मई 2023 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए कुछ शहरी क्षेत्रों/ नगरों के जल स्तर के आंकड़ों की तुलना मई महीने के दशकीय (2013-2022) औसत से की गई है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि मानीटरिंग किए गए लगभग 58.9% कुओं के भूजल स्तर में वृद्धि हुई है और 41.1% कुओं में जल स्तर में अधिकांशतः 0-2 मीटर की गिरावट पाई गई है। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): विभिन्न उपयोगों के लिए स्वच्छ जल की बढ़ती मांग के कारण हो रही निरंतर निकासी, वर्षा की अनिश्चितता, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि के कारण शहरी क्षेत्रों सहित देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।

जल राज्य का विषय है, स्थायी भूजल प्रबंधन सहित वर्षा जल के संचयन हेतु प्रभावी प्रयास राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है, हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिन्हें निम्नलिखित वेब-लिंक पर देखा जा सकता है
<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2023/02/2023021742.pdf>

भारत सरकार द्वारा देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2019 में 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में प्रथम जेएसए की शुरुआत की गई थी, जो वर्ष 2021, 2022 (पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) के दौरान भी जारी रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुनः उपयोग संरचनाओं के निर्माण, गहन वनीकरण और जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से मानसून वर्षा जल का संचयन करना है। दिनांक 04 मार्च 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा "पेयजल के लिए स्रोत स्थायित्वता" विषय के साथ वर्ष 2023 के लिए जेएसए का शुभारंभ किया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है।

केंद्र सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्यों के सहयोग से गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जल की कमी वाले क्षेत्रों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन करना है।

कृषि क्षेत्र में भूजल के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में से एक है, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के साथ सहभागी भूजल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, फसल चक्र, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग, बेहतर तकनीकों के उपयोग से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, नहर आधारित प्रणाली आदि के माध्यम से सतही जल के उपयोग को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जिसमें परियोजना और अपेक्षित निवेश संबंधी व्यापक रूपरेखा शामिल है। इस मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिससे 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल की उपलब्धता होगी। मास्टर योजना को उपयुक्त उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 तैयार किए गए हैं। एमबीबीएल के अनुसार, 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक के भूखंड आकार वाली सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन के प्रस्ताव को अनिवार्यतः शामिल किया गया है। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन उपनियमों की विशेषताओं को अपनाया है।

(घ) से (च): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से तीन शहरों यथा अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में एक अध्ययन शुरू किया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण और जल संतुलन पर भूमि उपयोग पैटर्न में आए परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन/निर्धारण किया जा सके।

**"शहरी क्षेत्र में भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 20.07.2023 को लोक सभा में उतर दिये जाने वाले
अतारंकित प्रश्न संख्या 184 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

देश के शहरी क्षेत्रों में माध्य [मई (2013 से 2022) और मई 2023] के साथ भूजल स्तर में दशकीय उतार-चढ़ाव

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शहर का नाम	विश्लेषित कूपों की संख्या	वृद्धि						गिरावट						वृद्धि		गिरावट	
				0-2 मी		2-4 मी		>4 मी		0-2 मी		2-4 मी		>4 मी		संख्या	%	संख्या	%
				संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%				
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	3	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
2		विशाखापत्तनम	16	7	43.8%	1	6.3%	1	6.3%	5	31.3%	2	12.5%	0	0.0%	9	56.3%	7	43.8%
3	असम	गुवाहाटी	34	12	35.3%	3	8.8%	1	2.9%	13	38.2%	3	8.8%	2	5.9%	16	47.1%	1	52.9%
4	बिहार	पटना (फेरेटिक)	6	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%
5	छत्तीसगढ़	भिलाई	6	2	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	2	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%
6		रायपुर	6	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	5	83.3%
7	दिल्ली	दिल्ली	84	31	36.9%	11	13.1%	18	21.4%	12	14.3%	6	7.1%	6	7.1%	60	71.4%	2	28.6%
8	गुजरात	अहमदाबाद	3	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%
9		गांधीनगर	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
10		सूरत	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
11		वडोदरा	4	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	1	25.0%
12	हरियाणा	अंबाला	35	18	51.4%	2	5.7%	1	2.9%	8	22.9%	2	5.7%	4	11.4%	21	60.0%	1	40.0%
13		फरीदाबाद	3	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
14		यमुनानगर	15	7	46.7%	2	13.3%	0	0.0%	5	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	9	60.0%	6	40.0%
15	चंडीगढ़	चंडीगढ़	15	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	3	20.0%	2	13.3%	7	46.7%	8	53.3%
16	झारखंड	धनबाद	2	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
17		जमशेदपुर	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
18		रांची	13	11	84.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	12	92.3%	1	7.7%
19	कर्नाटक	बैंगलोर	18	11	61.1%	2	11.1%	2	11.1%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	15	83.3%	3	16.7%
20	केरल	कन्नूर	6	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%
21		कोच्चि	3	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%
22		कोल्लम	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%
23		कोझिकोड	10	8	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	80.0%	2	20.0%
24		मलप्पुरम	6	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%
25		तिरुवनंतपुरम	5	2	40.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	2	40.0%
26		त्रिशूर	12	7	58.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	7	58.3%	5	41.7%
27		मध्य प्रदेश	भोपाल	15	4	26.7%	1	6.7%	0	0.0%	8	53.3%	1	6.7%	1	6.7%	5	33.3%	1
28	ग्वालियर		1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
29	इंदौर		20	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	40.0%	8	40.0%	1	5.0%	3	15.0%	1	85.0%

30		जबलपुर	17	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	11	64.7%	2	11.8%	1	5.9%	3	17.6%	1	82.4%
31	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	6	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	3	50.0%	3	50.0%
32		मुंबई शहर	6	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	83.3%
33		मुंबई उपनगर	17	5	29.4%	1	5.9%	0	0.0%	11	64.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	35.3%	1	64.7%
34		नागपुर	70	46	65.7%	13	18.6%	5	7.1%	6	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	64	91.4%	6	8.6%
35		नासिक	3	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	2	66.7%
36		पुणे	13	8	61.5%	0	0.0%	1	7.7%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	69.2%	4	30.8%
37	ओडिशा	भुवनेश्वर	41	22	53.7%	2	4.9%	1	2.4%	14	34.1%	2	4.9%	0	0.0%	25	61.0%	1	39.0%
38	पंजाब	अमृतसर	12	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	66.7%	1	8.3%	0	0.0%	3	25.0%	9	75.0%
39		जालंधर	13	2	15.4%	2	15.4%	0	0.0%	4	30.8%	2	15.4%	3	23.1%	4	30.8%	9	69.2%
40		लुधियाना	14	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	7	50.0%	3	21.4%	0	0.0%	4	28.6%	1	71.4%
41		मोहाली	7	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	71.4%	2	28.6%
42		पटियाला	16	2	12.5%	1	6.3%	1	6.3%	3	18.8%	4	25.0%	5	31.3%	4	25.0%	1	75.0%
43	राजस्थान	बीकानेर	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
44		जयपुर	12	1	8.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	8	66.7%	2	16.7%	1	83.3%
45		जैसलमेर	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
46		जोधपुर	5	3	60.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%
47		कोटा	2	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
48	तमिलनाडु	चेन्नई	18	11	61.1%	4	22.2%	2	11.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	17	94.4%	1	5.6%
49		कोयंबटूर	6	3	50.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%
50		मदुरै	11	1	9.1%	4	36.4%	6	54.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	0	0.0%
51		तिरुचिरापल्ली	6	2	33.3%	1	16.7%	1	16.7%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%
52		वेल्लोर	3	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%
53	तेलंगाना	हैदराबाद	36	12	33.3%	4	11.1%	9	25.0%	9	25.0%	1	2.8%	1	2.8%	25	69.4%	1	30.6%
54	उत्तर प्रदेश	आगरा	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
55		इलाहाबाद	4	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%
56		गाज़ियाबाद	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
57		कानपुर	7	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	71.4%	2	28.6%
58		लखनऊ	3	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
59		मेरठ	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
60		वाराणसी	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
61	उत्तरांचल	देहरादून	45	20	44.4%	5	11.1%	3	6.7%	13	28.9%	0	0.0%	4	8.9%	28	62.2%	1	37.8%
62	पश्चिम	कोलकाता	24	1	4.2%	1	4.2%	2	8.3%	10	41.7%	8	33.3%	2	8.3%	4	16.7%	2	83.3%
कुल			771	325	42.2	67	8.7	62	8.0	214	27.8	58	7.5	45	5.8	454	58.9	3	41.1
